

प्रेषक,

डा० एम० सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी,
272, फेस-2, वसंत विहार,
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून दिनांक: 21 मई, 2007

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (NeGP) के अंतर्गत **Common Services Centres (CSCs)**—जन सेवा केंद्रों का कियान्वयन।

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के पूर्व पत्र संख्या 105/ 300-सू0प्रौ0/XXXIV/06 दिनांक 03.04.07 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पत्रांक 1334/2006/PMU/ITDA दिनांक 02/12/2006 द्वारा प्रेषित की गई संस्तुति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

1. भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (National e-Governance Plan-NeGP) तैयार की है। यह योजना केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2006 को पारित की गयी है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवायें एकीकृत रूप से घर-घर तक कम मूल्य पर देना है। इस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारत में 1 लाख जन सेवा केंद्र मार्च 2008 तक स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप देना है। उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में 2625 (दो हजार छः सौ पच्चीस) Common Services Centres (CSCs) दिसम्बर 2007 तक स्थापित किये जायेंगे।

2. प्रत्येक जन सेवा केंद्र में कम्प्यूटर प्रिंटर, स्कैनर, यू0पी0एस0, टी0वी0 डिजीटल वेब कैमरा और ब्राड बैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में प्रोजेक्शन सिस्टम, टेलीमेडीसन आदि उपकरण भी शामिल किये जायेंगे।

1-

3. इस योजना को PPP (Public Private Partnership) मोड में क्रियान्वित किया जाना है। इसके क्रियान्वयन हेतु निजी Franchisee देने वाली संस्था अर्थात Service Centre Agency (SCA) का चयन राज्य सरकार द्वारा निविदा के माध्यम से किया जायेगा। Service Centre Agency फिर गांवों में जन सूचना केंद्रों का ग्रामीण उद्यमी (Village Level Entrepreneur-VLE) को आवंटन करेगा जो इनके प्रबंधन को पूर्व परिभाषित स्थानों पर करेगा। सरकारी विभागों की G2C सेवा और अन्य कई सेवा प्रदाताओं की सेवाएँ CSCs नेटवर्क पर उपलब्ध होंगी।

4. उत्तराखण्ड राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार अगले 4 वर्षों तक उत्तराखण्ड सरकार को 2625 CSCs हेतु ₹0 1652/- प्रति CSC प्रति माह की दर से ₹0 5,20,38,000/- प्रति वर्ष देगी, जो कि इन CSCs को प्रोत्साहन के रूप दिया जायेगा। शेष धनराशि (अधिकतम ₹0 5,20,38,000.00) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम व्यय किये जाने की व्यवस्था है, अतः शेष धनराशि (अधिकतम ₹0 5,20,38,000/-) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त करने एवं साथ ही योजना के सामान्य केन्द्रीय सहायता को जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य आदि अन्य प्रदेशों की भाँति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही भी की जाय।

5. राज्य में इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा निम्नवत् सुनिश्चित किया जाय।

(क) Service Centre Agency चयन के लिये उत्तरांचल राज्य को तीन इकाईयों में विभक्त कर निविदाएँ आमंत्रित की जानी प्रस्तावित हैं। एक निविदा-दाता को दो इकाई ही दी जा सकेंगी। यह बिड इकाईयों निम्नानुसार हैं:-

- (1) बिड इकाई 1- देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी।
- (2) बिड इकाई 2- पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर।
- (3) बिड इकाई 3- नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंहनगर, चम्पावत।

(ख) तदनुसार CSCs पर उपलब्ध कराई जाने वाली ई-गवर्नमेंट एवं अन्य सेवाओं के लिए आम नागरिकों के द्वारा निम्नवत् शुल्क सेवादाता (Service Centre Agency/Village Level Entrepreneur's Share) को दिया जायेगा :-

Type of Transaction	Charge to citizen	GoUA's share	SCA/VLE's share	Utility provider to pay
Utility Collections	Rs. 0/-	Rs. 0/-	Rs. 4/-	Rs. 4/-
Land Records & E-Government Services	Rs. 10/- for first page and Rs. 2/-per page subsequent pages	Rs. 0/-	Rs. 10/-for 1 st page+Rs. 2/-per page for subsequent pages	Rs. 0/-

h

(यह शुल्क सरकार द्वारा लिये जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त देय होगा)

(ग) उपरोक्त दरों तथा भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी। स्वीकृत निविदा उस निविदादाता की होगी जिसने प्रति CSC न्यूनतम सहायता राशि की मांग की होगी। अधिकतम देय सहायता राशि ₹0 3304/- होगी।

(घ) रेवेन्यू ऑफसेट पर निर्णय:- CSC पर हुई आय में से व्यय घटाकर शुद्ध राजस्व की गणना की जा सकती है। इस शुद्ध राजस्व व आय के अनुपात को राजस्व Offset का नाम दिया गया है।

$$\text{Revenue Offset\%} = \frac{\text{Total Income} - \text{Total Expenses}}{\text{Total Income}} \times 100$$

राजस्व Offset को सफल निविदादाता द्वारा मांगी गई सहायता राशि में से घटाने के पश्चात शेष राशि सहायता के रूप में दी जायेगी।

इस Offset की दर 50% प्रस्तावित है। IL&FS द्वारा विभिन्न राज्यों में Offset की दर निम्नांकित बताई गई हैं:-

क.	हरियाणा	-0%
ख.	झारखंड एवं पश्चिम बंगाल	-70%
ग.	पंजाब	-90%

ऑफसेट के संबंध में उदाहरण संलग्नक Annexure में उपलब्ध है। ऑफसेट की दर शून्य प्रतिशत होने का अभिप्राय है कि प्रत्येक CSC पर होने वाली आय व व्यय को बराबर मान लिया गया है (लाभ = 0) तथा निविदा में मांगी गई पूर्ण सहायता Service Centre Agency/Village Level Entrepreneur को दी जायेगी।

(ङ) Service Centre Agency द्वारा Village Level Entrepreneur को दिया जाने वाला हिस्सा निविदा के दौरान Service Centre Agency द्वारा दर्शाया जायेगा। Village Level Entrepreneur को दी जाने वाली न्यूनतम धनराशि ₹0 1500/- प्रतिमाह होगी।

(च) CSCs का नाम “उत्तरा” (Uttara) रखा जायेगा।

(छ) SCA को प्रथम चार वर्षों के लिए SWAN की Band Width निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

(ज) भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप विभिन्न विभागों से समयबद्ध रूप से ई-सेवायें प्राप्त करने हेतु अनुबन्ध (MOU) किया जायेगा ताकि इन CSC से पर्याप्त आय हो सके। भविष्य में ई-सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि से CSCs और भी लाभान्वित होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति सं० 79/XXXII(2)/2007 के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(डा० एम० सी० जोशी)
अपर सचिव।

संख्या: 160/XXXIV/300/(सू०प्रौ०)/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मंडलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(हरिओम)
उप सचिव।

८.